

†[THE PRIME MINISTER AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JAWAHARLAL NEHRU): (a)

**Technical Training**

Scheme	No.	Amount
		Rs.
(i) Technical Cooperation Scheme of the Colombo Plan	10	1,20,754.00
(ii) Third Country Programme of U.S. AID	11	Not known.
(iii) Others		Information is being collected.

**Military Training.**—Information is being collected.

(b) The entire cost of training under the Colombo Plan is borne by India as indicated under column (3) in answer to part (a) of the question. The entire cost of training under the US AID is borne by the U.S. Government. Information relating to technical and military training provided to Ceylon officials not covered under the Colombo Plan or the US AID is being collected.]

**REVIEW OF PATTERN OF ASSISTANCE FOR KHADI DEVELOPMENT**

241. SHRI M. P. BHARGAVA: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state whether any decision has been taken to appoint a committee to review the pattern of assistance given for Khadi development work?

THE MINISTER OF INDUSTRY IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI N. KANUNGO): The Estimates Committee has recommended the appointment of such a Committee. The matter is under the consideration of Government.

**GOVERNMENT PRINTING PRESSES**

242. SHRI M. P. BHARGAVA: Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state:

(a) the number of printing presses run by Government in Delhi and elsewhere in the country;

(b) whether any Government printing is done in any other presses; and

(c) what is the system followed in placing orders with non-governmental presses?

THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI MEHR CHAND KHAMNA): (a) Two at Delhi and eight elsewhere in the country.

(b) Yes, as the capacity of the Government presses is not sufficient to meet the demand.

(c) Generally through call of tenders from privately owned presses.

गोम्रा, दमन और ड्यू में बेरोजगारी

२४३. श्री भगवत नारायण भागवत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि गोम्रा, दमन और ड्यू में कितने लोग बेरोजगार हैं, और

(ख) यदि हां, तो उन्हें काम पर लगाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

†[UNEMPLOYMENT IN GOA, DAMAN AND DIU

243. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have made enquiries about the number of unemployed persons in Goa, Daman and Diu; and

(b) if so, what measures have been taken or are proposed to be taken by Government to provide employment to them?]

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री**  
(श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) और (ख)

जी हा । पुर्तगाली सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कुछ सरकारी और अर्ध-सरकारी सस्‍थानों का बन्द करने के कारण लगभग ३,००० व्यक्ति बेरोजगार हो गये थे । इनमें लगभग २,००० गोआनी नैतिक थे । इनमें से कुछ व्यक्तियों का फिर से काम पर लगा दिया गया है । गोआ में एक जगार दफ्तर भी खोल दिया गया है । इसके अलावा गोआ, दमन और ड्यू के औद्योगिक विकास के निम्ने कदम उठाए जा रहे हैं ताकि रोजगार को नई दिनाये खुल सके ।

†[THE PRIME MINISTER AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JAWAHARLAL NEHRU) (a) and (b) Yes, Sir Nearly 3,000 persons were rendered unemployed due to the closure of certain Government and semi-Government establishments maintained by the Portuguese Government These included about 2,000 Goan soldiers Some of these persons have since been re-employed An Employment Exchange has also been opened in Goa Moreover, steps are being taken for industrial development of Goa, Daman and Diu in order to provide avenues of employment]

**भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित हो जाने के कारण सरकार को मिलने वाली भूमि**

२४४. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या योजना आयोग ने देश में ऐसी भूमि के, जो अधिकतम सीमा निर्धारित

हो जाने के कारण राज्य सरकारों को मिलेगी, कोई आकड़े इकट्ठे किये हैं, और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' हो, तो इस प्रकार कितनी भूमि उपलब्ध हो सकेगी और यह किस प्रकार प्रयोग में लाई जायेगी ?

†[LAND ACCRUING TO GOVERNMENT AS A RESULT OF CEILING ON HOLDINGS]

244 SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission have collected statistics of land that will accrue to State Governments as a result of the fixation of ceiling on land holdings in the country, and

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, how much land will be available in this way, and how it will be utilized?]

**योजना तथा श्रम और सेवानियोजन**

**मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) (क)**

और (ख) भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण से संबंधित कानून हाल ही में बना है । इस कानून के कार्यान्वयन में प्रगति होने पर फालतू भूमि के बारे में आकड़े उपलब्ध होंगे । प्राप्त जानकारी के अनुसार जम्मू तथा काश्मीर में राज्य सरकार ने ४ ५ लाख एकड़ फालतू भूमि को ले लिया है और उस भूमि को जिन कृषकों के पास वह पहले से थी उस में तथा विस्थापित लोगों में बांट दिया है । पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार ने २.७ लाख एकड़ फालतू कृषि भूमि को ले लिया है । अन्तिम रूप से निम्न द्वारा होने तक यह भूमि बटाई पर खेती करने वाले और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सालाना आधार पर पट्टे पर दी जा रही है । जैसे जैसे कानून के कार्यान्वयन का काम आगे बढ़ेगा, और भूमि उपलब्ध हो